

इलाहाबाद यू0पी0 ग्रामीण बैंक का प्राथमिकता क्षेत्र में योगदान का अध्ययन

अतुल कुमार द्विवेदी

शोध छात्र (वाणिज्य), महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना(म0प्र0)

ARTICLE DETAILS

Article History

Published Online: 15 April 2019

Keywords

भारतीय अर्थव्यवस्था, कुरुक्षेत्र, योजना।

ABSTRACT

कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की केन्द्र बिंदु है व भारतीय लोगों के जीवन की धुरी है। कृषि आर्थिक जीवन का प्रमुख आधार है व रोजगार का मुख्य स्रोत है। यदि कृषि को देश की आधारशिला कह दिया जाए तो गलत नहीं होगा। देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग आधा भाग कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित क्षेत्रों से ही अपना जीवन यापन कर रही है। अतः कृषि के विकास से ही भारत देश का विकास निर्भर करता है। भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र का विकास करने व किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने हेतु अनेक नीतियों का निर्माण किया गया है। कृषि के विकास में वित्त की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने उचित व सही समय पर, कम ब्याज दरों पर साख की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत साख की व्यवस्था को प्राथमिकता दी है। इसके लिए सहकारी साख व्यवस्था, व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना प्रमुख हैं।

प्रस्तावना—

21वीं शताब्दी में भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के हालातों में बहुत अधिक बदलाव नहीं हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र को अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत निवास करने वाले व्यक्तियों के रोजगार का मुख्य साधन व जीवन यापन करने का महत्वपूर्ण स्रोत कृषि है। भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे बड़ा क्षेत्र कृषि क्षेत्र है। भारत देश की अधिकांश जनसंख्या कृषि से ही अपनी जीविका चलाती है। देश के क्षेत्रफल के सर्वाधिक भूमि पर खेती की जाती है। देश की राष्ट्रीय आय में कृषि तथा कृषि से सम्बन्धित क्रियाओं का योगदान बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। प्रायः भारत देश की राष्ट्रीय आय में प्राथमिकता क्षेत्र व प्राथमिकता क्षेत्र के कृषि एवं उससे सम्बन्धित क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान होता है। कृषि एक तरफ भारत की अधिकांश जनसंख्या के आजीविका का मुख्य साधन है व दूसरी तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था का एक सुदृढ़ आधार है। अर्थव्यवस्था का कृषि क्षेत्र देश के औद्योगिक विकास में भी सहायक होता है। अर्थव्यवस्था में यदि कृषि क्षेत्र के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि की जाती है, तो विपणन योग्य कृषि अतिरेक में भी वृद्धि होती है जिसके कारण ही ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के आय में वृद्धि होती है। कृषि क्षेत्र में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छे उर्वरक, अच्छे संयन्त्र एवं औजार, ट्रैक्टर, पम्पिंग सेट व सिंचाई की सुविधाओं आदि की आवश्यकता होती है। प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में इन सब का अभाव अधिकांश किसानों के पास होता है। देश की उत्पादन क्षमता का एक बड़ा भाग कृषि सम्पत्तियों के रूप में होता है। इनमें सिंचाई के साधनों का विकास प्रमुख है। प्रत्येक वर्ष कृषकों के पास सिंचाई के संसाधनों के विकास हेतु सरकार व ग्रामीण बैंक सहायता

प्रदान करते हैं। कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था का सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के कारण ही एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों में व कृषि से सम्बन्धित कार्यों में लगे अधिकांश व्यक्तियों के पास वित्त की कमी होती है। वे व्यक्ति वित्त के अभाव के कारण ही कृषि में अपनी विभिन्न कृषि सुविधाओं का विकास नहीं कर पाते हैं। जिस कारण कृषि का उत्पादन भी प्रभावित होता है अर्थात् उत्पादकता कम होती है। भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कृषि कार्यों में लगे हुए परिवारों को संस्थागत स्रोतों से पर्याप्त वित्त उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने संस्थागत स्रोतों का विकास किया ताकि संस्थागत स्रोत भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता क्षेत्र को, मुख्यतः कृषि क्षेत्र को वित्त उपलब्ध कराके, किसानों की वित्त सम्बन्धी समस्या को हल कर सकें। जिससे किसान कृषि हेतु अपनी विभिन्न कृषि मशीनों को खरीद सकें व सिंचाई की सुविधाओं का विकास कर सकें, ताकि उनके कृषि उत्पादन में वृद्धि हो व उनके जीवन स्तर में भी सुधार हो, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी को हटाने के लिए कृषि का विशेष महत्त्व है क्योंकि कृषि के विकास के कारण ही किसानों की आय में वृद्धि होगी और किसान कृषि आय के माध्यम से गरीबी को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए साख के संस्थागत स्रोतों द्वारा सन्तुलित ऋण वितरण की नीति को अपनाना एवं उसका पालन करना भी आवश्यक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों को व किसानों को समुचित व समय पर वित्त उपलब्ध करा रहे हैं।

समक व समय –

अध्ययन हेतु प्रायः उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में कार्यरत इलाहाबाद यू0पी0 ग्रामीण बैंक को चुना गया है। इलाहाबाद यू0पी0 ग्रामीण बैंक उत्तर प्रदेश के 11 जनपदों में कार्यरत है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में अपनी सेवाएँ दे रहा है। अध्ययन हेतु प्रायः इलाहाबाद यू0पी0 ग्रामीण बैंक की वार्षिक प्रतिवेदन से प्राप्त वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 के आँकड़ों का प्रयोग किया गया है। समामेलन के कारण 1 अप्रैल 2019 से इलाहाबाद यू0पी0 ग्रामीण बैंक की शाखाएँ आर्यावर्त बैंक के नाम से कार्य करेंगी।

अध्ययन हेतु उद्देश्य –

इलाहाबाद यू0पी0 ग्रामीण बैंक द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र में बाँटे गये ऋण का अध्ययन करना।

इलाहाबाद यू0पी0 ग्रामीण बैंक की उपलब्धियाँ –

यथा 31 मार्च 2018 को इलाहाबाद यू0पी0 ग्रामीण बैंक की कुल 650 शाखाएँ कार्यरत हैं, जिनमें 526 ग्रामीण शाखाएँ हैं।

1. कुल वितरित ऋण

बैंक द्वारा कुल वितरित किए गए ऋण को तालिका संख्या-1 के माध्यम से समझा जा सकता है-

तालिका संख्या-1

इलाहाबाद यू0पी0 ग्रामीण बैंक द्वारा कुल वितरित किए गए ऋण की स्थिति
(रु0 करोड में)

वर्ष	बैंक द्वारा कुल वितरित किया गया ऋण
2015-16	3234.18
2016-17	3019.44
2017-18	2482.88

स्रोत-वार्षिक प्रतिवेदन – इलाहाबाद यू0पी0 ग्रामीण बैंक

तालिका संख्या-1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि बैंक ने वर्ष 2015-16 के दौरान 3234.18 करोड़ रुपये, वर्ष 2016-17 के दौरान 3019.44 करोड़ रुपये व वर्ष 2017-18 के दौरान कुल 2482.88 करोड़ रुपये ऋण वितरित किया है।

2. प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित ऋण

बैंक द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित किए गए ऋणों को तालिका संख्या-2 के माध्यम से समझा जा सकता है।

तालिका संख्या-2

इलाहाबाद यू0पी0 ग्रामीण बैंक द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित किए गए ऋण की स्थिति
(रु0 करोड में)

वर्ष	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित किया गया ऋण	कुल वितरित किए गए ऋण से प्रतिशत
2015-16	3116.57	96.36
2016-17	2890.03	95.71
2017-18	2289.85	92.23

स्रोत-वार्षिक प्रतिवेदन – इलाहाबाद यू0पी0 ग्रामीण बैंक

तालिका संख्या-2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि बैंक द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र में वर्ष 2015-16 में 3116.57 करोड़ रुपये, वर्ष 2016-17 में 2890.03 करोड़ रुपये व वर्ष 2017-18 में 2289.85 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है। तालिका के अवलोकन से यह भी पता चल रहा है कि बैंक द्वारा वितरित किए गए कुल ऋण में से वर्ष 2015-16 में 96.36 प्रतिशत ऋण, वर्ष 2016-17 में 95.71 प्रतिशत ऋण व वर्ष

2017-18 में 92.23 प्रतिशत ऋण प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित किया गया है।

3. कृषि क्षेत्र व सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र में वितरित ऋण

बैंक द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित किए गए ऋण में से कृषि क्षेत्र में व सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र में वितरित किए गए ऋण का विवरण तालिका संख्या 3 में स्पष्ट है-

तालिका संख्या-3
बैंक द्वारा कृषि क्षेत्र व सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र में वितरित ऋण

(रु० करोड में)

वर्ष	कृषि क्षेत्र में वितरित ऋण		बैंक द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र में वितरित किया गया ऋण
	बैंक द्वारा कृषि क्षेत्र में वितरित किया गया ऋण	प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित किए गए ऋण से प्रतिशत	
2015-16	2912.26	93.44	195.14
2016-17	2496.23	86.37	385.50
2017-18	2039.22	89.06	237.38

स्रोत-वार्षिक प्रतिवेदन – इलाहाबाद यू०पी० ग्रामीण बैंक

तालिका संख्या-3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि बैंक द्वारा कृषि क्षेत्र में वर्ष 2015-16 में 2912.26 करोड रुपये, वर्ष 2016-17 में 2496.23 करोड रुपये व वर्ष 2017-18 में 2039.22 करोड रुपये का ऋण वितरित किया गया है। बैंक द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र में भी वर्ष 2015-16 में 195.14 करोड रुपये, वर्ष 2016-17 में 385.50 करोड रुपये व वर्ष 2017-18 में 237.38 करोड रुपये का ऋण वितरित किया गया है।

निष्कर्ष –

तालिका संख्या-2 के अध्ययन से स्पष्ट है कि इलाहाबाद यू०पी० ग्रामीण बैंक ने कुल वितरित किए गए ऋण में से प्रतिवर्ष 90 प्रतिशत से अधिक का ऋण प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित किया हुआ है व तालिका संख्या-3 के अध्ययन से स्पष्ट है कि प्राथमिकता क्षेत्र में वितरित किए गए ऋण में से प्रतिवर्ष 85 प्रतिशत से अधिक का ऋण कृषि क्षेत्र में वितरित किया हुआ है।

सन्दर्भ सूची –

1. आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था – डॉ० किरन सिंह, दीप बुक एजेन्सी, इलाहाबाद
2. योजना – नई दिल्ली
3. कुरुक्षेत्र – नई दिल्ली
4. वार्षिक प्रतिवेदन – इलाहाबाद यू०पी० ग्रामीण बैंक (2015-16, 2016-17, 2017-18)